

[2023] 4 एस. सी. आर. 473

/

डेल्मा लुबना कोएल्हो बनाम।

एडमंड क्लिट फर्नांडीस

(स्थानांतरण याचिका (सी) 2021 की संख्या 1475) अप्रैल 18,2023

/

[राजेश बिंदल और अरविंद कुमार, जे. जे.]

स्थानांतरण याचिका-पति द्वारा पारिवारिक न्यायाधीश, मंगलुरु, कर्नाटक के समक्ष तलाक याचिका दायर की गई थी-कनाडा की स्थायी निवासी पत्नी द्वारा दायर वर्तमान याचिका, जो वर्तमान में मुंबई, महाराष्ट्र में स्थित है, जिसमें तलाक याचिका को मंगलुरु, कर्नाटक से बांद्रा, मुंबई, महाराष्ट्र में पारिवारिक न्यायालय में स्थानांतरित करने की मांग की गई थी-

आयोजित:याचिकाकर्ता कनाडा की स्थायी निवासी है-वह वर्ष 2014 में वहाँ स्थानांतरित हुई थी और वहाँ एक अच्छी तनखाह वाली नौकरी पर काम कर रही थी, हालाँकि, वैवाहिक गठबंधन के लिए भारत आई थी-चूँकि याचिकाकर्ता कनाडा की स्थायी निवासी है, इसलिए उसे नियमित रूप से विदेश यात्रा करनी चाहिए-वह मध्यस्थता प्रक्रिया के दौरान कनाडा में थी और कार्यवाही में ऑनलाइन भाग लेती थी-दोनों पक्ष अच्छी तरह से शिक्षित हैं और अपनी नौकरियों और व्यवसायों में लगे हुए हैं-याचिकाकर्ता मामले की सुनवाई में भाग लेने के लिए मंगलुरु की यात्रा कर सकता है और जब भी आवश्यक हो उपस्थिति से छूट भी ले सकता है-कर्नाटक से महाराष्ट्र में याचिका के हस्तांतरण के लिए कोई मामला नहीं बनाया गया-भारत का संविधान-अनुच्छेद 142।

/

/

/

वैवाहिक मामले-स्थानांतरण याचिकाएं-आयोजित:वैवाहिक मामलों में स्थानांतरण याचिकाओं की संख्या दर्ज की जाती है, मुख्य रूप से पत्नियों द्वारा पति द्वारा शुरू की गई वैवाहिक कार्यवाही के हस्तांतरण की मांग करते हुए-आम तौर पर, सर्वोच्च न्यायालय महिलाओं के प्रति नरमी दिखाते हुए की गई प्रार्थना को स्वीकार करता रहा है-हालाँकि, इस नरमी का महिलाओं द्वारा दुरुपयोग किया जा रहा था-इसलिए, प्रत्येक मामले पर अपने गुण-दोष के आधार पर विचार किया जाना चाहिए।

/

/

आर. श्रीनिवास कुमार बनाम आर. शमिता **(2019) 9 एससीसी 409:[2019] 12 एस. सी. आर. 873;** मुनीश कक्कड़ बनाम निधि कक्कड़

(2020) 14 एससीसी 657:[2019] 15 एससीआर 169-प्रतिष्ठित।

अनिदिता दास बनाम श्रीजीत दास (2006) 9 एस. सी. सी. 197-पर भरोसा किया।

/

473 ए.

474 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2023] 4 एस. सी. आर.

संथिनी बनाम विजय वेंकटेश **(2018) 1 एससीसी 1:[2017]**

12 एस. सी. आर. 557-संदर्भित।संदर्भित निर्णय

[2019] 12 एससीआर 873

विशिष्ट पैरा **9**

[2019] 15 एससीआर 169

विशिष्ट पैरा **9**

/

[2017] 12 एससीआर 557

संदर्भित

पैरा **22**

नागरिक मूल न्यायनिर्णय:2021 की स्थानान्तरण याचिका (सी) संख्या 1475।

कर्नाटक के मंगलुरु में माननीय परिवार न्यायाधीश के 2021 के एम. सी. No.331 को बांद्रा, मुंबई, महाराष्ट्र में परिवार न्यायालय में स्थानान्तरित करने के लिए उच्चतम न्यायालय के नियमों के आदेश XXXVI बी के साथ पठित नागरिक प्रक्रिया संहिता की धारा 25 और 151 के अंतर्गत याचिका।शंकर डिवेट, याचिकाकर्ता के लिए अधिवक्ता।

/

पाई अमित, सुश्री पंखुड़ी भारद्वाज, अभियुदय वत्स, अधिवक्ता।प्रत्यर्थियों के लिए।

/

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

राजेश बिंदल, जे।

1. वर्तमान याचिका याचिकाकर्ता-पत्नी द्वारा दायर की गई है जिसमें 2021 की एम. सी. संख्या 331 को "डॉ. एडमंड क्विंट फर्नांडीस बनाम" के रूप में स्थानांतरित करने की मांग की गई है। श्रीमती डेलमा लुबना कोएल्हो "कर्नाटक के मंगलुरु में परिवार न्यायाधीश के समक्ष बांद्रा, मुंबई, महाराष्ट्र में परिवार न्यायालय में लंबित हैं।

/

2. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि पक्षकारों ने दिसंबर, 2019 के महीने में फेसबुक पर मुलाकात की और उन्होंने अवर लेडी ऑफ मिरेकल्स चर्च, मंगलुरु में ईसाई संस्कारों और रीति-रिवाजों के अनुसार 05.12.2020 पर शादी कर ली।

/

3. यह दलील दी जाती है कि शादी के बाद, याचिकाकर्ता मंगलुरु में अपने वैवाहिक घर में प्रतिवादी के साथ रह रही थी, जहाँ प्रतिवादी और उसके परिवार के सदस्यों द्वारा उसके साथ दुर्व्यवहार, अपमान और अपमान किया गया था। उन पर हर चीज के लिए आरोप लगाया गया और उनके खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया गया। प्रतिवादी ने उसे 10-15 दिनों के लिए ब्रेक देने के बहाने, याचिकाकर्ता के लिए एकतरफा टिकट बुक किया और उसे 15.01.2021 पर मुंबई भेज दिया। इसके बाद उन्होंने सभी ए को काट दिया।

/

/

475

डेलमा लुबना कोएल्हो बनाम एडमंड क्विंट फर्नांडीस [राजेश बिंदल, जे.] ए.

उसके साथ संबंध। 05.07.2021 पर, कोविड-19 महामारी प्रतिबंधों में ढील दिए जाने के बाद, याचिकाकर्ता मंगलुरु वापस आ गया। हालाँकि, उसे प्रतिवादी और उसके परिवार के सदस्यों द्वारा उसके वैवाहिक घर में प्रवेश करने से मना कर दिया गया था। वह पूरी तरह से टूट गई थी। उसने मंगलुरु के पांडेश्वर पुलिस स्टेशन से संपर्क किया और शिकायत दर्ज कराई।

4. पुलिस अधीक्षक ने हस्तक्षेप किया और प्रतिवादी को पुलिस स्टेशन बुलाया। प्रतिवादी ने कहा कि वह पहले ही तलाक का नोटिस जारी कर चुका है और तलाक की मांग करने वाली उसकी याचिका दायर करने की प्रक्रिया में है। याचिकाकर्ता द्वारा बार-बार अनुरोध किए जाने के बावजूद, प्रतिवादी ने अपने तरीके नहीं बदले।

/

5. 06.08.2021 पर, उसने कानूनी नोटिस का जवाब देते हुए कहा कि वह अपने वैवाहिक घर में आने के लिए तैयार है और एक खुशहाल वैवाहिक जीवन जीना चाहती है। 10.08.2021 पर, उन्हें मंगलुरु में परिवार न्यायालय में दायर तलाक याचिका की प्रति के साथ अदालत का समन प्राप्त हुआ।

/

6. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने कहा कि वह मुंबई में अपने बूढ़े माता-पिता के साथ रह रही है। याचिका को लड़ने के लिए मुंबई से मंगलुरु तक उसके साथ जाने के लिए उसके घर पर कोई नहीं है, जो मुंबई से 1,000 किलोमीटर से अधिक दूर है। वह कन्नड़ भाषा भी नहीं जानती हैं। जबकि याचिका को मुंबई (महाराष्ट्र) में स्थानांतरित करने की स्थिति में प्रतिवादी को किसी भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। पार्टियाँ केवल लगभग 40 दिनों की अवधि के लिए एक साथ रहती थीं। याचिकाकर्ता द्वारा कहा गया है कि यदि उसे मौका दिया जाता है, तो वह शादी को फिर से करने की कोशिश करेगी। याचिकाकर्ता को एक बैंक में नौकरी करने के लिए मजबूर किया गया क्योंकि प्रतिवादी ने उसे आर्थिक रूप से समर्थन देने से इनकार कर दिया था। यदि वह सुनवाई में भाग लेने के लिए अक्सर मंगलुरु की यात्रा करती है, तो उसे अपनी नौकरी खोने का खतरा है। उसके लिए भी लागत वहन करना संभव नहीं होगा।

/

/

/

7. दूसरी ओर, प्रतिवादी के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि हालांकि पक्षकारों ने सोशल मीडिया पर मुलाकात की थी, उनकी शादी से एक साल पहले, वह कोविड-19 महामारी/प्रतिबंधों में ढील दिए जाने के बाद मंगलुरु भी गई थी और वे अक्सर मिलते थे। वह प्रतिवादी की पारिवारिक पृष्ठभूमि और उसके परिवार की स्थिति से भी अच्छी तरह वाकिफ थी। वास्तव में, विवाह के तुरंत बाद, याचिकाकर्ता का व्यवहार वैसा नहीं था जैसा विवाह से पहले था। प्रत्यर्थी अपने वृद्ध माता-पिता के साथ रहता है। वे पेशे से डॉक्टर हैं। प्रतिवादी परोपकारी गतिविधियों में शामिल एक वैश्विक स्वास्थ्य संगठन का संस्थापक और सीईओ भी है। शुरू में याचिकाकर्ता को इस पर गर्व था लेकिन बाद में

/

/

/

रवैया बदल गया।प्रत्यर्थी ने अपनी शादी से पहले भी याचिकाकर्ता की वित्तीय स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए इंजीनियरिंग ग्रेड के लिए पेशेवर शुल्क का भी भुगतान किया।उसने अब प्रतिवादी के माता-पिता के साथ दुर्व्यवहार किया क्योंकि वह एक शानदार जीवन जीना चाहती थी।शादी से पहले के सभी सकारात्मक बिंदु अब नकारात्मक थे।

8. वास्तव में, याचिकाकर्ता कनाडा का स्थायी निवासी होने के नाते, उस जीवन शैली का आदी था।शादी केवल प्रतिवादी के जीवन को खराब करने के लिए थी, हालांकि शुरू में यह दावा किया गया था कि वह भारतीय संस्कृति और परंपराओं से प्यार करती है।हालाँकि यह आरोप लगाया जाता है कि प्रतिवादी ने याचिकाकर्ता को वैवाहिक घर से बाहर कर दिया था, हालाँकि, बाहर जाना उसका अपना निर्णय था।मुंबई पहुँचने के तुरंत बाद, उन्होंने आईसीआईसीआई बैंक में नौकरी के लिए आवेदन किया और संगठन से अपना इस्तीफा 19.02.2021 पर भेज दिया, जहाँ वे प्रतिवादी के साथ काम कर रही थीं।वह 05.04.2021 में बैंक में नौकरी में शामिल हुई थी।प्रत्यर्थी द्वारा विवाह को फिर से संपन्न करने के लिए कई प्रयास किए गए लेकिन कोई परिणाम नहीं निकला और मध्यस्थता के प्रयास भी विफल रहे।

/

/

/

9. प्रत्यर्थी को उसके और उसके परिवार द्वारा खरीदे गए नए फ्लैट की कीमत '2,00,00,000/- (केवल दो करोड़ रुपये) के बारे में भी अंधेरे में रखा गया था।प्रतिवादी को पते के बारे में तब पता चला जब उसने महिला पुलिस स्टेशन में 06.07.2021 पर शिकायत दर्ज कराई।प्रतिवादी द्वारा दायर तलाक याचिका के प्रतिवाद के रूप में, याचिकाकर्ता ने वैवाहिक अधिकारों की बहाली के लिए याचिका दायर की है।उन्होंने आगे कहा कि यह विवाह के अपरिवर्तनीय टूटने का मामला है क्योंकि बार-बार मध्यस्थता के दौरान भी, पक्षकार सुलह नहीं कर सकते थे।यह न्यायालय भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के अंतर्गत पक्षों की सहमति के बिना तलाक दे सकता है।रिलायंस को इस न्यायालय के फैसलों पर रखा गया है

/

आर. श्रीनिवास कुमार बनाम आर. शमिता (2019) 9 एससीसी 409 और मुनीश कक्कड़ बनाम निधि कक्कड़ (2020) 14 एससीसी 657।

/

10. कई अन्य तर्क भी गुण-दोष पर उठाए गए थे, हालांकि, मामले के हस्तांतरण के लिए याचिकाकर्ता की प्रार्थना पर विचार के सीमित उद्देश्य के लिए, उन पर अधिक विस्तार से ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है।

/

11. सुनवाई के समय, याचिकाकर्ता व्यक्तिगत रूप से उपस्थित था जबकि प्रतिवादी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हुआ था।

12. पक्षकारों और पक्षकारों के लिए व्यक्तिगत रूप से विद्वान परामर्श सुना। 13. शादी 05.12.2020 पर हुई थी। पार्टियाँ केवल 15.01.2021 तक अपने वैवाहिक घर में एक साथ रहती थीं।

/

477

डेलमा लुबना कोएल्हो बनाम एडमंड क्विंट फर्नांडेस [राजेश बिंदल, जे.] ए.

/

14. दिनांक 1 के आदेश के अवलोकन से, यह स्पष्ट है कि वैवाहिक विवाद के निपटारे की संभावना होने के कारण, मामले को सर्वोच्च न्यायालय मध्यस्थता केंद्र को भेजा गया था। 04.03.2022 पर इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश में अभिलेख किया गया है कि मध्यस्थता के प्रयास विफल रहे। प्रत्यर्थी ने न्यायालय को संतुष्ट करने के लिए शपथपत्र दायर करने के लिए समय मांगा कि विवाह का अपरिवर्तनीय टूटना है और इस न्यायालय को विवाह को भंग करने के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के अंतर्गत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करना चाहिए।

/

15. 25.03.2022 पर इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश में अभिलेख है कि पक्षों के बीच विवाद के समाधान के लिए मध्यस्थता के माध्यम से एक और प्रयास करने की आवश्यकता थी। इसे महाराष्ट्र राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण को भेजा गया था। विवाह परामर्शदाता को भी संबद्ध होना आवश्यक था। 16. इस न्यायालय द्वारा 02.09.2022 पर पारित आदेश इस प्रकार है:

/

“ ऐसा प्रतीत होता है कि विवाह ने प्रारंभिक अवधि से ही काम नहीं किया है। फेसबुक पर मिलने के बाद दोनों ने शादी कर ली।

/

समस्या यह है कि पत्नी क्या माँगती है और पति क्या कहता है वह भुगतान करने में सक्षम है।

दोनों पक्षों को चल/अचल संपत्तियों की सूची के साथ शपथ पत्र दाखिल करने दें। उन्हें अपने पिछले तीन वर्षों के आयकर रिटर्न भी दाखिल करने चाहिए।

/

आवश्यक शपथ पत्र दाखिल करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया जाता है। 29 सितंबर, 2022 को सूची बनाएँ।

पक्ष या तो न्यायालय में उपस्थित रहेंगे या वस्तुतः संपर्क करेंगे जिसके लिए रजिस्ट्री द्वारा कनेक्शन प्रदान किया जाएगा। "

/

17. दिनांकित 13.10.2022 आदेश से, यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता कनाडा में काम कर रही होगी क्योंकि उसने कहा कि उसने कनाडा में अपना काम समाप्त कर दिया है और अब वह भारत में रह रही है। वे एक विवाह सलाहकार की सहायता लेने के लिए सहमत हुए। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एस. जे. वजीरुल्लाह को मध्यस्थ नियुक्त किया गया था। मध्यस्थ से रिपोर्ट प्राप्त हुई है जिसमें कहा गया है कि विभिन्न सत्रों में लगभग 50 घंटे बिताने के बावजूद, पक्ष और उनके परिवार के सदस्य एक समझौते पर नहीं पहुंच सके और 08.02.2023 की रिपोर्ट के अनुसार मध्यस्थता विफल रही। यह विशेष रूप से मध्यस्थ द्वारा अपनी रिपोर्ट में दर्ज किया गया है।

/

/

478

/

[2023] 4 एस सी आर।

कि चार महीनों के दौरान, पक्षों के साथ कई बैठकें हुईं और याचिकाकर्ता कनाडा में थी और वह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठकों में भाग लेती थी।

18. वैवाहिक मामलों में स्थानांतरण याचिकाओं की संख्या मुख्य रूप से पत्नियों द्वारा दायर की जाती है जो पति द्वारा शुरू की गई वैवाहिक कार्यवाही के हस्तांतरण की मांग करती हैं। यह न्यायालय आम तौर पर महिलाओं के प्रति नरमी दिखाते हुए की गई प्रार्थना को स्वीकार करता रहा है। अनिदिता दास बनाम श्रीजीत दास (2006) 9 एस. सी. सी. 197 में, इस न्यायालय ने कहा कि हो सकता है कि इस नरमी का महिलाओं द्वारा दुरुपयोग किया जा रहा हो। इसलिए, प्रत्येक मामले पर उसके गुण-दोष के आधार पर विचार किया जाना चाहिए।

/

19. हाथ में इस मामले के तथ्यों में, याचिकाकर्ता कनाडा का स्थायी निवासी है। वह वर्ष 2014 में वहाँ स्थानांतरित हो गई थी और वहाँ एक अच्छी तनख्वाह वाली नौकरी पर काम कर रही थी, हालाँकि, वैवाहिक गठबंधन के लिए भारत आई थी। वह वर्तमान में अपने माता-पिता के साथ मुंबई, महाराष्ट्र में रहती है और आईसीआईसीआई बैंक में काम करती है। विवाह से कोई बच्चा पैदा नहीं होता है। दोनों पक्षों के फेसबुक पर मिलने के बाद संबंध शुरू हुए। जहाँ तक प्रत्यर्थी का संबंध है, वह पेशे से एक डॉक्टर है और कर्नाटक के मंगलुरु में रह रहा है। पति ने मंगलुरु में तलाक की याचिका दायर की है, जहाँ वह अपने बूढ़े माता-पिता के साथ रहता है। इसके बाद, पत्नी ने मुंबई, महाराष्ट्र में वैवाहिक अधिकारों की बहाली के लिए एक याचिका दायर की।

/

/

/

20. पक्षों की स्थिति और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि यह पत्नी द्वारा दायर एक याचिका है जिसमें पति द्वारा दायर मामले को मंगलुरु, कर्नाटक से मुंबई, महाराष्ट्र में स्थानांतरित करने की मांग की गई है, हमारे विचार में याचिका को मंगलुरु, कर्नाटक से मुंबई, महाराष्ट्र में स्थानांतरित करने के लिए कोई मामला नहीं बनाया गया है। पत्नी कनाडा की स्थायी निवासी है। वह नियमित रूप से विदेश यात्रा कर रही होगी। जैसा कि न्यायमूर्ति एस. जे. वज़ीफदार द्वारा प्रस्तुत दिनांक 1 की मध्यस्थता रिपोर्ट में टिप्पणियों से स्पष्ट है, याचिकाकर्ता मध्यस्थता प्रक्रिया के दौरान कनाडा में था और ऑनलाइन कार्यवाही में भाग लिया। शादी से पैदा होने वाले किसी भी बच्चे की देखभाल नहीं की जानी चाहिए। दोनों दल अच्छी तरह से शिक्षित हैं और अपनी नौकरियों और व्यवसायों में लगे हुए हैं। वह मामले की सुनवाई में भाग लेने के लिए मंगलुरु की यात्रा कर सकती है और जब भी आवश्यकता हो उपस्थिति से छूट भी ले सकती है। हालाँकि, वर्तमान में, अभिलेख पर आई सामग्री के आधार पर पक्षों की वित्तीय स्थिति को देखते हुए, हम यह नहीं पाते हैं कि याचिकाकर्ता को मंगलुरु की यात्रा के लिए खर्च का भुगतान करने के लिए प्रतिवादी को निर्देश जारी करने के लिए कोई आधार बनाया गया है। हालाँकि, फिर भी अगर वह खर्चों की प्रतिपूर्ति की मांग करना चाहती है, तो ए

/

/

/

वह संबंधित न्यायालय के समक्ष आवेदन दायर करने के लिए स्वतंत्र होगी, जिसकी योग्यता के आधार पर जांच की जा सकती है।

21. हम इसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के अंतर्गत शक्ति के प्रयोग के लिए एक उपयुक्त मामला नहीं पाते हैं क्योंकि पक्षों पर अच्छी समझ हो सकती है। वे केवल 40 दिनों तक एक साथ रहे थे। शादी में बसने में समय लगता है। प्रत्यर्थी के विद्वान वकील द्वारा जिन निर्णयों पर भरोसा किया गया है, वे अलग-अलग हैं क्योंकि उन मामलों में कार्यवाही तलाक की कार्यवाही में नीचे के न्यायालय ों द्वारा निर्णय के बाद इस न्यायालय तक गई थी, जहां पक्षों ने पुराने वैवाहिक विवाद में साक्ष्य का नेतृत्व किया था। अभिलेख पर पर्याप्त सामग्री थी और जिस आधार पर भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के अंतर्गत शक्ति का प्रयोग करते हुए विवाह को भंग किया गया था, वह विवाह का अपरिवर्तनीय विघटन था जो अन्यथा हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 में विवाह को भंग करने का आधार नहीं है।

/

/

22. जहाँ तक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पक्षों की उपस्थिति का संबंध है, इस न्यायालय द्वारा मामले में पर्याप्त मार्गदर्शन दिया गया है।

/

संथिनी बनाम विजय वेंकटेश (2018) 1 एस. सी. सी. 1 का मामला।

23. ऊपर वर्णित कारणों से, हम वर्तमान याचिका में कोई योग्यता नहीं पाते हैं। तदनुसार इसे खारिज कर दिया जाता है।

दिव्या पांडे

याचिका खारिज कर दी गई।

/

(सहायक: श्रद्धा सिंह और शेवाली मोंगा, एलसीआरए)

/

/

/